

नरिभया फंड के लिये 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालयों हेतु नरिभया फंड में 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी।

प्रमुख बढि

- राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है तथा महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में नरितर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नरिभया फंड में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मशिन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट) नरिभया फंड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पोक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की फंडिंग की जाती है।
- इस फंड हेतु गहलोत सरकार ने 40.27 करोड़ रुपए राज्यनधिभद में एवं 19.73 करोड़ रुपए केंद्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे इन पोक्सो न्यायालयों में पदस्थापति कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का नरिबाध आहरण हो सकेगा।